of 3% on net fixed assets. The fixation of tariff for supply of power by the State Electricity Boards is within the jurisdiction of the Boards/State Governments concerned. With a view to improving the overall performance of the SEBs, State Power Ministers have resolved to adopt co efficiency based power tariff, including the minimum agricultural tariff of 50 paise per kwh.

R.E.C.'s. Financing of Project under Energy Conservation Scheme in Meerut

1705. SHRI SOM PAL : Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) what is the total cost of project whcih was sanctioned and financed by R.E.C. for district Meerut, U.P. in 1989 under Energy Conservation Scheme and whether the project was completed in time;

(b) whether it is also a fact that R.E.C. would have given grant to U.P.S.E.B., if the project had got completed in time, if so, whether the project got completed in time;

(c) if not, the reasons therefor and whether extension of time was given to complete the project so that loan to U.P.S.E.B. could be converted into grant;

(d) if so, the reasons therefor;

(e) what improvement in transmission losses has been there after completion of this project;

(f) whether the equipments installed in this project are functioning well;

(g) whether proper record is being maintained to monitor the equipments installed for this project;

(h) whether the material which was purchased against this project was diverted to other works by U.P.S.E.B.; and

(i) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : (a) to (i) The Rural Electrification Corporation had sanctioned 4 projects for the purpose of conservation of Energy in Network (reduction of line losses, etc.) for the district of Meerut, amounting to a total of Rs. 384.96 lakhs. The entire amount was converted into grant after completion of the project. Although threre was delay in completion of the projects, it was completed within the extended period of the sanction. The projects being new and innovative in nature, the State Electricity Board had taken more time than originally envisaged for procuring certain equipments included in the project.

On evaluation, it has been assessed that savings in line losses effected per annum worked out to 97 lakhs units which is considered to be satisfactory. As per reports received from UPSEB, the equipments have been functioning well. At the time of the evaluation of the projects, proper records of the equipments were being maintained and there was no indication of any equipments meant for the projects having been diverted.

मध्य प्रदेश और उड़ीसा में विद्युत उत्पादन इकाइयां

1706. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और उड़ीसा में 31 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार खराब हालत के कारण बन्द पड़ी विद्युत उत्पादन इकाईयों की जिलेवार संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) इन इकाईयों को फिर से चालू करने, इन्हें बदलने और नई तथा अधिक क्षमता वाली इकाईयां स्थापित किए जाने के लिए जिलेवार प्राप्त हुए प्रस्तावों की संख्या कितनी-कितनी है और 31 जनवरी, 1992 तक उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन दोनों राज्यों में विद्युत उत्पादन की कितनी इकाईयां हैं और किन इकाईयों की विद्युत उत्पादन हेतु उपयोगी जीवन अवधि समाप्त हो चुकी है और आगामी तीन वर्षों में किन-किन इकाईयों की जीवन अवधि की निर्धारित सीमा समाप्त हो रही है और उनके लिए किए जाने वाले वैकल्पिक प्रबंधों का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) से (ग) : 31-1-1992 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा में निम्नलिखित ताप विद्युत एवं जल-विद्युत यूनिट काफी लम्बी अवधि तक बन्द रहे थे :—

मध्य प्रदेश	
ताप विद्युत	
कोरबा-1 केन्द्र	—16-6-89 से बन्द
सतपुड़ा-2	—22-7-91 से बन्द
अमरकंटक	—31-5-90 से बंद
जल-विद्युत	—शून्य
उड़ीसा	
ताप विद्युत	—शून्य
जल-विद्युत	
अपर कोरबा-1	—31-1-92 की स्थिति के अनुसार प्रचालन में नहीं है ।

कोरबा-1 केन्द्र की कार्याविधि 1 अगस्त, 1992 को समाप्त हो गई है और सतपुड़ा तथा अमरकंटक केन्द्रों के उपर्युक्त यूनिटों को समकालित किया जा चुका है । देश में विभिन्न यूनिटों की कार्याविधि बढ़ाए जाने संबंधी कार्यक्रम आरंभ किया गया है । जब भी आवश्यक होगा, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के ताप विद्युत यूनिटों के लिए भी कार्याविधि विस्तार संबंधी अध्ययन किए जाएंगे ।

मध्य प्रदेश में अमरकंटक, कोरबा तथा सतपुड़ा स्थित ताप विद्युत केन्द्रों और उड़ीसा में तलचेर ताप विद्युत केन्द्र एवं हीराकुड ज० वि० केन्द्र के संबंध में एक नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम आरंभ किया जा रहा है ।

गढ़वाल, उत्तर प्रदेश में बिजली के बिलों की अदायगी के लिए अधिक कार्यालय

1707. **श्री राम गोपाल यादव** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पौड़ी गढ़वाल जिले में बिजली के बिलों का भुगतान करने के लिए कितने कार्यालय हैं जहां पर बिजली बिलों के लिए भुगतान स्वीकार किया जाता है;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि लोगों को बिलों का भुगतान करने के लिए सतपुली या पौड़ी जाना पड़ता है, जो कि मन्यार स्यूं क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत दूर पड़ता है तथा उन्हें इसमें बहुत असुविधा होती है, और

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में थड़ियाल तथा अन्य स्थानों पर कुछ और कार्यालय खोलने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के अनुसार बिजली के बिलों से संबंधित नकद भुगतान की राशि पौड़ी जिले में विभिन्न स्थानों यथा पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर, कालागढ़, जहरीखाल (लैण्डस डाउन), सतपूली, नौ गांवखाल, पोखरा, थैलीसैण, बाबा बाजार, देवप्रयाग आदि पर एकत्र की जाती है । नकदी एकत्र करने और उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए बोर्ड जिला पौड़ी गढ़वाल के दूर-दिराज के क्षेत्रों में कैम्प भी लगता है । नकदी एकत्र करने के लिए नए काउन्टर खोलने का कोई प्रस्ताव इस समय उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के विचाराधीन नहीं है ।

Participation of Asea Brown Boveri in Power Projects

1708. SHRI MENTAY PADMANABHAM : Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) whether Asea Brown Boveri has submitted any proposals for setting up of or participation in power projects in India;

(b) if so, the details of the proposals; and

(c) the terms and conditions thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : (a) to (c) The